

प्रेषक,

विभापुरी दास,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग, देहरादून दिनांक 16 मई 2007

विषय:- "विश्व पर्यावरण दिवस" दिनांक 05 जून 2007 को मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि 05 जून, 2007 को "विश्व पर्यावरण दिवस" के रूप में मनाया जाता है। शासन द्वारा इस वर्ष भी 05 जून, 2007 को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में उत्साह पूर्वक एवं अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए मनाये जाने का सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है।

1. इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNDEP) द्वारा " **Melting Ice-A Hot Topic** " थीम निश्चित की गई है। पर्यावरण के विभिन्न अवयवों में स्वच्छ जल, वर्षा जल, जल संचय, जल श्रोतों का संरक्षण तथा जल का न्यायपूर्ण वितरण विशेष महत्व रखते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु इस प्रकार की जनसहभागिता सुनिश्चित करनी होगी जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक सिद्ध होगी। पर्यावरण संरक्षण की भावना को जागरूक करने के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विभिन्न शिक्षण संस्थाएं, स्वैच्छिक संस्थाएं एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान कार्य कर रहे हैं एवं विभिन्न परियोजनायें भी इससे सम्बन्धित गतिविधियों में सम्मिलित हैं।
2. जैसा कि आप अवगत हैं कि पॉलीथीन का चलन तथा कैंरी बैग्स का प्रचलन न केवल नगरों में वरन् प्रदेश के सुदूरवर्ती गाँवों में भी फैल गया है। इन थैलियों का प्रयोग बाजार में विभिन्न औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थानों/इकाईयों द्वारा लाखों की संख्या में प्रतिदिन किया जा रहा है। इस प्रकार विगत दो-तीन दशकों से पॉलीथीन थैलियों का

प्रचलन शनैः शनैः इस प्रकार बढ़ता गया कि आज स्थिति यह हो गई है कि थैलियाँ यत्र-तत्र बिखरी हुई देखी जा सकती हैं। ज्ञातव्य है कि पॉलीथीन एक अजैविक (Non-Biodegradable) पदार्थ है। जिसका क्षरण कई दशकों तक भी नहीं हो पाता है। जिसके फलस्वरूप इस पॉलीथीन के कचरे से एक ओर नालों/सीवन लाइन का बहाव अवरुद्ध हो जाता है वहीं पशुओं के द्वारा इन्हें खा लिये जाने से उनकी मृत्यु भी हो जाती है।

3. अतः आज यह अतिआवश्यक है कि राज्य में शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी पॉलीथीन के दुष्प्रभाव से मुक्त करने के लिए प्रभावी कार्यवाही के रूप में इसके प्रयोग को शनैः शनैः कम किया जाय तथा इसके सुरक्षित निस्तारण के बारे में जनसाधारण में जागरूकता लाई जाय।
4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में दिनांक 05 जून, 2007 पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जायेगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सर्वश्रेष्ठ पंचायतों का चयन कर पुरस्कृत भी किया जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या 113/07/XII/90(11)/2006 दि० 2 अप्रैल, 2007 के प्रस्तर 4 एवं 5 में निम्नवत् व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित की गयी है:-

प्रस्तर 4- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की उक्त सुसंगत धाराओं के अधीन सार्वजनिक स्थलों, जलाशयों, नदी, नालों से प्लास्टिक एवं पॉलीथीन बैग आदि की गंदगी हटवाने का कष्ट करें ताकि राज्य में पर्यावरण संरक्षण किया जा सके।

प्रस्तर 5- राज्य के प्रत्येक जनपद में सम्बन्धित जिला पंचायत द्वारा निम्नानुसार निर्देश भी जारी किए जाएं।

- (क) **ग्रामीण क्षेत्रों में होटलों, धर्मशाला, आश्रम, लॉज, बारातघर, बैंकिंग हॉल :-** ग्रामीण होटल एवं ठहरने वाले समस्त स्थानों के प्रबन्धक अपने प्रतिष्ठान के कूड़े को अपनी व्यवस्था से सूखा कूड़ा यथा प्लास्टिक, कागजद्व कोच, मेटल कन्टेनर आदि अगलनशील पदार्थ एवं गीला कूड़ा यथा फलों सब्जियों के छिलके तथा बचा हुआ समस्त खाद्य पदार्थ, पेड़ पौधों की टहनियाँ एवं पत्ते आदि गलनशील पदार्थ को पृथक-पृथक एकत्र करेंगे। अजैविक अवशिष्ट का एकत्रीकरण नियमित रूप से किया जायेगा। प्रतिष्ठानों में एकत्रित सूखे कूड़े को जिला पंचायतों द्वारा साप्ताहिक रूप से

एकत्रित कर पुर्नचक्रण हेतु भेजने की व्यवस्था की जायेगी तथा गलनीशील पदार्थों जैसे फलों के छिलके, बचे हुए समस्त खाद्य पदार्थ आदि को अपने परिसर में ही कम्पोस्टींग कर उन्हें खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाय। उक्त हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई Code of practice की प्रतिलिपि संलग्न है।

जिन प्रतिष्ठानों में गीले कूड़े के निस्तारण हेतु स्थान उपलब्ध नहीं है वहाँ जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण सड़कों के किनारे रखे गये कूड़ेदान को प्रयोग में लाया जायेगा। इन स्थानों पर ऐसे कूड़ेदान की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा की जायेगी।

(ख) ग्रामीण हाट बाजार एवं मानवीय क्रियाकलापों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान:-

(1) प्लास्टिक मैनुफैक्चर्स सेल्स एंड यूजेज रूल्स, 1999 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दुकानदारों द्वारा 20 माइक्रोन से कम मोटाई का प्लास्टिक बैक विक्रय एवं उपयोग एवं भण्डारण करना प्रतिबन्धित है तथा 8" X 12" (20 सेमी0 X 30 सेमी0) या उससे छोटे प्लास्टिक कैरीबैग का विक्रय/उपयोग एवं भण्डारण भी पूर्णतया प्रतिबन्धित है। उक्त प्राविधान का व्यापक प्रचार प्रसार ग्रामीण हाटों तथा बाजारों में किया जाय ताकि इन वस्तुओं के उपयोग तथा निषेध के सम्बन्ध में जानकारी जनसामान्य को हो सके। उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षक एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार प्रतिका प्लास्टिक वेस्ट मनेजमेंट की प्रतिलिपि संलग्न है।

(ग) स्कूल एवं संस्थायें :- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थानों में ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन की व्यवस्था शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य एवं छात्रावास के प्रबन्धकों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत के माध्यम से छात्र/छात्राओं की जैविक एवं अजैविक कूड़े को इसके उत्पादक स्थल पर पृथक एकत्र करने का प्रशिक्षण दिया जाय।

5. प्रत्येक ग्राम पंचायत में जैविक अवशिष्ट हेतु कूड़ेदान का नीले रंग का डिब्बा तथा अजैविक हेतु लाल रंग के डिब्बे का प्रयोग सार्वजनिक स्थल पर रख कर किया जाय।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालय एवं राजकीय कार्यालयों में भी उपरोक्तानुसार स्वच्छता के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
7. ग्राम पंचायत में उपरोक्तानुसार कूड़ादान रखे जाने के सम्बन्ध में खंड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी शत-प्रतिशत सत्यापन कराते हुए प्रमाण-पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी/जिला पंचायत को प्रस्तुत करेंगे।
8. प्रत्येक जनपद की जिला पंचायत द्वारा दि० 21.05.07 तक उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षक एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उक्त तिथि से पूर्व ग्राम पंचायत, विकास खंड एवं जनपद स्तर की बैठकें सुनिश्चित की जायेगी।
9. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा दि० 26.05.07 तक प्लॉस्टिक/पॉलीथीन निर्धारित स्थल पर एकत्रित किया जायेगा।
10. जिलाधिकारी प्रत्येक पंचायत के लिए इस प्रकार के अजैविक अपशिष्ट के संग्रह के लिए स्थल निर्धारित करेंगे। इन स्थलों का निर्धारण इस प्रकार किया जाये कि अपशिष्ट को पुर्नचक्रण के लिए भेजने में आसानी हो। यथासंभव ऐसे स्थल मोटर मार्गों के आसपास होने चाहिए ताकि एकत्रित अपशिष्ट पुनः न बिखरे ओर उसका परिवहन कराया जा सके। जिलाधिकारी पुर्नचक्रण हेतु स्थापित इकाईयों से सम्पर्क कर इस अपशिष्ट का मूल्य निर्धारित करा लेंगे। सामान्यतः यह मूल्य रु० 3.00 प्रति कि०ग्रा० से कम नहीं होगा। अपशिष्ट का एकत्रीकरण तथा पुर्नचक्रण इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग होगा। अतः इसके निमित्त जिला पंचायत राज अधिकारी का नोडल अधिकारी बना दिया जाय। जिला पंचायत राज अधिकारी संग्रह स्थलों के चयन, अजैव अपशिष्ट का संग्रह, परिवहन तथा पंचायतों का धन का भुगतान आदि पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। एकत्रित प्लॉस्टिक का मूल्य रु० 3.00 प्रति कि०ग्रा० होगा जिसका भुगतान ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. संग्रह स्थल पर एकत्रित होने वाले व जैविक, पदार्थों की पुष्टि खंड विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतवार की जायेगी। प्रत्येक खंड विकास अधिकारी निर्धारित स्थान तक अपशिष्ट पहुँचाने की व्यवस्था

करेंगे। इस पर होने वाला व्यय अपशिष्ट की बिक्री से प्राप्त होने वाले धन से किया जायेगा।

12. जनपद स्तर पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्र पंचायतवार कूड़े की मात्रा का सत्यापन किया जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत द्वारा भी पृथक से अपना सहयोग दिया जायेगा। प्रत्येक जिला पंचायत द्वारा आकलित मात्रा का सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित एक समिति जिसमें असरकारी सदस्य होंगे के द्वारा किया जायेगा तथा निर्धारित तिथि 02.06.07 को उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित समिति के माध्यम से अजैविक कूड़े का आकलन कर सर्वोत्कृष्ट पंचायतों को दि० 05.06.07 को पुरस्कार की घोषणा की जायेगी।
13. प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ जनपद को उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षक एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा। चूँकि उक्त अभियान प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से किया जायेगा। अतः इसमें समस्त पंचायतों की भूमिका अनिवार्य होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित सार्वजनिक स्थलों पर इसी प्रकार जैविक/अजैविक कूड़े का निस्तारण कर पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत स्थल पर स्वयं सेवी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं एवं राजकीय विभागों को भी सम्मिलित किया जा सकता है जो विश्व पर्यावरण दिवस के सफल एवं उद्देश्यपूर्ण आयोजन में सहयोग करेंगे।
14. मीडिया, संचार माध्यमों से जनपद स्तर पर मनाये जौन वाले कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय जिससे कि जनसामान्य में पर्यावरण संरक्षण के प्रति उत्तरदायित्व बोध हो सके।
15. विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को केवल 05 जून तक ही सीमित न रखा जाय बल्कि इसका आयोजन इस प्रकार किया जाय कि वे यथावश्यकता आगे भी चलते रहें ताकि आम जनता में ऐसी भावना उत्पन्न हो कि पर्यावरण संरक्षण/संवर्द्धन उनका प्रमुख दायित्व/कर्तव्य भी हो।
16. उक्त व्यवस्था पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण सप्ताह के सम्बन्ध में की जा रही है। आप अवगत है कि ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में प्रायः नित्य ही संचार माध्यमों में वैज्ञानिक रिपोर्टों का उल्लेख रहता है। यह स्पष्ट है कि हिमालयी क्षेत्र में तापमान बढ़ने

से हिमनदों के पिघलने की गति तीव्र हुई है। इन क्षेत्रों में इन दुष्प्रभावों के लिए एक सीमा तक अजैविक अपशिष्ट भी उत्तरदायी है।

अजैविक अपशिष्टों के संग्रह एवं उसके निस्तारण की उक्त प्रणाली एक निरन्तर प्रक्रिया के रूप में प्रदेश के प्रमुख यात्रा मार्गों पर चलाना नितान्त आवश्यक है। प्रदेश में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुण्ड, पूर्णागिरि आदि धार्मिक महत्व के स्थलों के अतिरिक्त पिण्डारी, नामिक सुन्दरढूंगा ग्लेशियरों, मसूरी, नैनीताल आदि पर्यटक स्थलों तथा उनके आसपास पर्यटकों का आवागमन पूरे वर्ष बना रहता है। परिणाम स्वरूप इन अपशिष्टों का दुष्प्रभाव भी इन क्षेत्रों में सर्वाधिक रहता है।

इन क्षेत्रों से अपशिष्ट को हटाने के लिए प्रत्येक स्थल के सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार कर ली जाय। उक्त उल्लिखित स्थल केवल उदाहरण मात्र है। जनपदों की परिस्थितियों के आधार पर जनपदवार स्थलों का निर्धारण कर लिया जाय। जनपद की समेकित कार्य योजना शासन को भी उपलब्ध कराई जाय।

इन चयनित क्षेत्रों में अजैविक अपशिष्टों को हटाने उनका परिवहन तथा पुर्नचक्रण के लिए भेजने का कार्य दि० 25.05.07 से 10.06.07 तक एक अभियान के रूप में किया जायेगा। इस अवधि में अजैविक अपशिष्ट हटाने के लिए प्रत्येक स्तर की पंचायत के स्तर पर बैठक कर जागरण अभियान भी चलाया जायेगा। चिन्हित स्थल चूंकि यात्रा मार्गों एवं पर्यटक मार्गों पर होंगे इसलिए यद्यपि क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से यह क्षेत्र छोटे होंगे किन्तु अपशिष्ट की अधिक मात्रा का संग्रहण इन क्षेत्रों में हो सकेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि इन क्षेत्रों के सामान्य निवासी भी पर्यटन गतिविधियों में लगे होते हैं। अतः अपशिष्ट के संग्रहण एवं पर्यावरण के प्रदूषण मुक्त होने को विचार के स्तर पर उनके रोजगार से जोड़ने के लिए विचार गोष्ठियों को भी अभियान का अंग बनाया जा सकता है। यह भी प्रयास किया जाय कि इन चयनित स्थलों को अभियान की अवधि में अजैविक अपशिष्ट से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाय ताकि इन अपशिष्टों के हटने से आने वाला अन्तर जन-सामान्य तथा सामान्य पर्यटक को भी स्पष्ट दिखाई दे सके। अभियान के संचालन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा पशुपालन विभाग का विशेष उपयोग हो सकता है। अतः इन विभागों का सहयोग इस अवधि में लिया जाय।

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम के प्राविधानों के अनुसार ठोस अपशिष्टों को जलाने पर प्रतिबन्ध है। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि नगर निकायों में कूड़ा एकत्रण कर इसे जला दिया जाता है। इस हेतु नगर निकायों एवं पंचायतों में अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए जायें कि वे अपने

अधीनस्थ सफाई कर्मचारियों को इस बात की जानकारी दें कि एकत्रित कूड़ों को जलाना प्रतिबन्धित है तथा वे इस तरह के कूड़ों को न जलायें।

उक्त अभियान की अवधि में अभियान के उद्देश्यों एवं जनसामान्य से अपेक्षाओं का व्यापक प्रचार किया जाय तथा अपशिष्ट सहित तथा अपशिष्ट मुक्त स्थलों के फोटोग्राफ भी प्रदर्शन हेतु रखे जाय।

चूँकि यह कार्य मिशन के रूप में निरन्तर किया जाना है अतः इसमें पंचायतों के साथ ही जन प्रतिनिधियों, पर्यावरणविदों, शिक्षाविदों, शिक्षकों, छात्रों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का व्यापक सहयोग प्राप्त किया जाय। मासिक रूप से इन प्रकरण में की गयी कार्यवाही की समीक्षा भी कार्यक्रम की सफलता में सहायक हो सकेगी।

अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने तथा उक्त कार्यवाही से मासिक रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को अधिक सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव भी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया

विभा पुरी
(विभा पुरी दास)


प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या 113 /XII/ 90 (11)/ 2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
11. निदेशक, पशुपालन उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

13. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
14. संयुक्त निदेशक, पंचायत प्रकोष्ठ, पंचायती राज निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
15. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
16. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पंचायती राज, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
18. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, को इस आशय से प्रेषित कि कृपया, पत्र में इंगित बिन्दुओं पर सभी नगर निकायों से आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।
19. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव।